राम चन्द्र सिंह

बनाम

सावित्री देवी और अन्य।

9 अक्टूबर 2003

[वी.एन. खरे, मुख्य न्यायाधीश और एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति]

*दीवानी प्रक्रिया संहिता-धारा 11-***पूर्वनिर्णीत***-उत्तरदाताओं द्वारा बैंक को ऋण चुकाने में चूक-विचारण न्यायालय द्वारा बैंक के पक्ष में डिक्री-उत्तरदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय में प्रथम अपील-अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता के पक्ष में गिरवी रखी गई भूमि की नीलामी बिक्री का निष्पादन-उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच सहमति के आधार पर किश्तों में डिक्री राशि का भुगतान करने का निर्देश-नीलामी बिक्री को दबाने और धोखाधड़ी करने के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका-* **पूर्वनिर्णय** *के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा याचिका खारिज:--वैधता - अभिनिर्धारित, वैध नहीं है चूँकि सहमति आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और अपीलकर्ता अपील का पक्षकार नहीं था - इसलिए, इसे बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया।*

उत्तरदाता 2 ने उत्तरदाता बैंक से 95.20 एकड़ ज़मीन गिरवी रखकर ऋण लिया था। भुगतान न करने पर, बैंक ने विचारण न्यायालय में एक वाद दायर किया जिसमें ऋण राशि, बकाया राशि और भविष्य के ब्याज सहित, और गिरवी रखी गई ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए एक प्रारंभिक डिक्री का दावा किया गया। बैंक द्वारा दायर वाद में, उत्तरदाता संख्या 2 **की बहन, अर्थात् उत्तरदाता संख्या** 1 **ने एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसने बंधक रखी गई भूमि में अपने हिस्से का दावा किया, जो कि उसके पक्ष में विभाजन वाद में पारित विचारण न्यायालय के प्रारंभिक डिक्री के आधार पर था। विचारण न्यायालय ने ऋण राशि,**

बकाया राशि और भविष्य के ब्याज सहित, बैंक के पक्ष में एक प्रारंभिक डिक्री पारित की। गिरवी रखी गई ज़मीनों में उत्तरदाता 2 के हिस्से की बिक्री के लिए भी एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। विचारण न्यायालय ने गिरवी रखी गई ज़मीनों की बिक्री के लिए एक अंतिम डिक्री पारित की।

उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए एक सहमति आदेश पारित किया जिसमें उत्तरदाताओं को बैंक को दो किश्तों में डिक्रीत राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। उत्तरदाताओं द्वारा डिक्रीत राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, बैंक ने गिरवी रखी गई भूमि की बिक्री के लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक निष्पादन आवेदन दायर किया। विचारण न्यायालय ने गिरवी रखी गई ज़मीन के एक हिस्से को नीलामी के ज़रिए बेचने का निर्देश दिया। उच्चतम बोलीदाता होने के नाते, निष्पादन न्यायालय ने अपीलकर्ता के पक्ष में नीलामी बिक्री की पुष्टि की और अपीलकर्ता ने तदनुसार बोली की राशि जमा कर दी। उत्तरदाताओं ने नीलामी बिक्री को **अपास्त** करने के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने नीलाम की गई ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की, इस आधार पर कि सहमति आदेश के अनुसार निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने समीक्षा याचिका स्वीकार कर ली और नीलामी बिक्री को अपास्त कर दिया।

अपीलकर्ता ने उत्तरदाता 1 के पक्ष में विभाजन के **वाद** में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री को अपास्त करने के लिए एक स्वत्व वाद दायर किया। अपीलकर्ता ने उत्तरदाता 1 के विभाजन वाद में विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया जिसमें कहा गया कि उत्तरदाता 1 द्वारा प्राप्त प्रारंभिक डिक्री मिलीभगत और कपटपूर्ण थी और इसलिए शुरू की गई अंतिम डिक्री कार्यवाही शून्य और अमान्य है; और उत्तरदाता 2 के पिता की मृत्यु 1944 में हो जाने के कारण, उत्तरदाता 2 ही गिरवी रखी गई भूमि का उत्तराधिकारी

था क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 बहुत बाद में लागू हुआ था। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के आवेदन को स्वीकार कर लिया।

उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय में एक दीवानी समीक्षा याचिका दायर की। अपीलकर्ता ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक दीवानी समीक्षा आवेदन दायर किया, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रथम अपील में पारित सहमति आदेश की समीक्षा की मांग की गई। यह अपील इस आधार पर दायर की गई थी कि अपील के पक्षकारों ने न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता को गिरवी रखी गई भूमि की नीलामी बिक्री के तथ्य को छुपाया था। उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं की दीवानी समीक्षा याचिका को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता के दीवानी समीक्षा आवेदन को *पूर्व-न्याय* के आधार पर खारिज कर दिया। अतः ये अपीलें।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं ने न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके उच्च न्यायालय से सहमति आदेश प्राप्त किया है और इसलिए उन्हें इसका लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती; और यह कि गिरवी रखी गई ज़मीनें उन्होंने नीलामी में तब खरीदी थीं जब उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील में उत्तरदाताओं को बैंक को दो किश्तों में डिक्रीत राशि का भुगतान करने के लिए सहमति आदेश पारित किया था और इसलिए सहमति आदेश अमान्य और शून्य है।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने प्रथम अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सहमति आदेश के अनुसार बैंक को डिक्रीटल राशि का भुगतान कर दिया है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए और मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. धोखाधड़ी हर गंभीर कार्य को दूषित कर देती है। धोखाधड़ी और न्याय कभी एक साथ नहीं रह सकते। धोखाधड़ी एक ऐसा आचरण है जो ·पत्र या शब्दों द्वारा, जो दूसरे व्यक्ति या प्राधिकारी को पूर्व के आचरण के जवाब में एक निश्चित निर्णायक रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है, शब्द या पत्र द्वारा। मिथ्याबयान स्वयं धोखाधड़ी के

बराबर है। निर्दोष मिथ्याबयान धोखाधड़ी के विरुद्ध राहत का दावा करने का कारण भी बन सकता है। एक कपटपूर्ण मिथ्याबयान को छल कहा जाता है और इसमें किसी व्यक्ति को जानबूझकर या लापरवाही से उसे झूठ पर विश्वास करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करके नुकसान पहुँचाना शामिल है। यदि कोई पक्ष ऐसे अभ्यावेदन करता है जिसे वह जानता है कि वह झूठा है और इससे नुकसान होता है, तो यह कानून में धोखाधड़ी है; भले ही जिस उद्देश्य से अभ्यावेदन किया गया था वह बुरा न रहा हो। न्यायालय में धोखाधड़ी के कृत्य को हमेशा गंभीरता से लिया जाता है। किसी संपत्ति के संबंध में दूसरों के अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से की गई मिलीभगत या साजिश, लेन-देन को शुरू से ही शून्य कर देगी। धोखाधड़ी और छल समानार्थी हैं। हालाँकि किसी दिए गए मामले में छल, धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता, लेकिन धोखाधड़ी सभी न्यायसंगत सिद्धांतों के लिए अभिशाप है और धोखाधड़ी से दूषित किसी भी मामले को *पूर्व-न्याय सिद्धांत* सहित किसी भी न्यायसंगत सिद्धांत के प्रयोग द्वारा कायम नहीं रखा जा सकता, या बचाया नहीं जा सकता। न्यायालयी कार्यवाही में धोखाधड़ी करके प्राप्त कोई भी आदेश कानून की दृष्टि में अमान्य है। [551-ई-एच, 554-ए, एफ, 559-सी]

1.2. उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा आदेश XXVI, नियम 13 और 14(2) और आदेश XX नियम 18 **दीवानी प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत दायर हस्तक्षेप आवेदन विचारणीय नहीं था क्योंकि ये न्यायालय को किसी प्रारंभिक डिक्री को इस आधार पर अपास्त करने का कोई अधिकार नहीं देते कि वह धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। उपरोक्त सिद्धांत से, उच्च न्यायालय को इस संबंध में अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र माना जाना चाहिए। (556-एफ)

राम प्रीति यादव बनाम उत्तर प्रदेश उच्च विद्यालय एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड एवं अन्य, **जे.टी. (2003) पूरक 1 एससी 25***; श्रीमती श्रीश धवन बनाम मेसर्स श्री शॉ ब्रदर्स,* **एआईआर (1992) एससी 1 555;** *एस.पी. चेंगलवरया नायडू बनाम जगन्नाथ,* **[1994] 1**

एसएससी 1; *इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,* **[1996] 5 एससीसी 550 और** *चितरंजन दास बनाम दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं अन्य,* **[99 सीडब्ल्यूएन 897] संदर्भित।**

डेरी बनाम पीक, **(1989) 14 एसी 337, संदर्भित।**

केर ऑन फ्रॉड एंड मिस्टेक; *बिगेलो ऑन फ्रॉडुलेंट कन्वेयन्सेज*; *आर्लिज एंड पैरी ऑन फ्रॉड*, **संदर्भित।**

1.3. एक बार जब यह अभिनिर्धारित कर लिया जाता है कि न्यायालय में धोखाधड़ी करके निर्णय और डिक्री प्राप्त की गई है, तो यह स्वाभाविक है कि *पूर्व-निर्णय* **के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा पारित पूर्व आदेशों का संदर्भ देकर एक गंभीर गलती की है जिससे अपीलकर्ता के लिए न्याय के द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। दीवानी समीक्षा याचिका में, उच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए था कि क्या नीलामी क्रेता के अधिकार को उसकी अनुपस्थिति में पारित सहमति आदेश के कारण अमान्य किया जा सकता था। अपीलकर्ता प्रथम अपील में पक्षकार नहीं था। वह समझौते का भी पक्षकार नहीं था। [557-एफ-एच]**

मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, **एआईआर (1962) एससी 527 और** *शारदा बनाम धर्मपाल, [2003] 4 एससीसी 493, का उल्लेख किया गया है।*

1.4. सहमति आदेश पक्षकारों के बीच एक समझौता है जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होती है। अपीलकर्ता ने समीक्षा आवेदन में कहा कि अपील के पक्षकारों ने नीलामी बिक्री और उसकी पुष्टि को छुपाया था। प्रथम अपील दायर करने के बाद घटित घटनाओं के प्रभाव, जिसके परिणामस्वरूप एक तृतीय पक्ष अधिकार का सृजन हुआ, को उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। किसी तृतीय पक्ष अधिकार को सहमति से अमान्य नहीं किया जा सकता। इसलिए, उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता के तर्क पर उनके उचित परिप्रेक्ष्य

में विचार करना आवश्यक था। उच्च न्यायालय अपने आदेश की समीक्षा के उद्देश्य से इन प्रश्नों पर स्वयं विचार करने के लिए बाध्य था। [558-ए-सी]

द्वारका प्रसाद अग्रवाल (डी) विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा एवं एक अन्य बनाम बी.डी. अग्रवाल एवं अन्य, **[2003) 6 एससीसी 230, पर अवलंबन किया गया।**

1.5. यद्यपि सहमति आदेश के अनुपालन में, उत्तरदाता ने राशि जमा कर दी थी और बैंक ने उसे विनियोजित कर लिया है, न्यायालय पर धोखाधड़ी के प्रभाव के संबंध में कानूनी मुद्दे पक्षकारों के आचरण के संबंध में अभी भी विचाराधीन हैं। इसलिए उच्च न्यायालय से पक्षों के बीच इक्विटी को समायोजित करने की अपेक्षा की जाती है। बैंक स्वयं को अनुचित रूप से समृद्ध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बंधक की प्रारंभिक डिक्री को लागू करते समय, वह नीलामी क्रेता की कीमत पर निर्णय-ऋणी से डिक्री राशि वसूलने का सहारा नहीं ले सकता है। उच्च न्यायालय *'न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचाएगा'* **के सिद्धांत पर भी ध्यान देने में विफल रहा। (559-डी-एफ)**

राजेश डी. दरबार एवं अन्य बनाम नरसिंगराव कृष्णाजी कुलकर्णी एवं अन्य, **जे. टी. (2003) 7 एस. सी. 209,संदर्भित।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील सं. 8216/2003।

पटना उच्च न्यायालय के दीवानी समीक्षा संख्या 1520/1997 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.12.98 से।

साथ में

सी.ए. सं. 8217/2003।

उपस्थित पक्षों की ओर से डॉ. जी.सी. भरुका, संजीव गोयल, देवाशीष भरुका, बी.के. सतीजा, एस.बी. उपाध्याय (एनपी), आर.एस. द्विवेदी, अजय कुमार, एस.आर. सेतिया, अजय चौधरी, (एनपी), अमित कुमार (एनपी), राम लाल रॉय, आर.एन. केशवानी।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया: अनुमति प्रदान की गई।

न्यायालय पर धोखाधड़ी का प्रभाव इन अपीलों में शामिल मूल प्रश्न है, जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी समीक्षा सं. 1520/1997 में पारित दिनांक 10.12.1998 और दीवानी समीक्षा सं. 245/1998 में पारित दिनांक 10.5.1999 के निर्णयों और आदेशों से उत्पन्न हुआ है।

उत्तरदाता सं. 2, अरुण प्रकाश पांडे (जिन्हें आगे 'बंधककर्ता' कहा जाएगा) ने भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लिया था, जिसके लिए भूमि बैंक के पक्ष में गिरवी रखी गई थी। वह ऋण चुकाने के मामले में चूककर्ता बन गया। बैंक ने 95.20 एकड़ की गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में प्रारंभिक डिक्री के साथ-साथ बकाया राशि और भविष्य के ब्याज सहित 1,15,312.62 रुपये की राशि का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में, गिरवीकर्ता की बहनें वादग्रस्त संपत्तियों में 6 आने शेयरों का दावा कर रही थीं, जो कथित रूप से उत्तरदाता सं. 1 द्वारा उक्त गिरवी रखी गई भूमि के संबंध में दायर किए गए दिनांक 19.7.1979 के विभाजन मुकदमे में पारित प्रारंभिक डिक्री पर या उसके आधार पर निर्भर होने का दावा कर रही थीं। उपरोक्त राशि के लिए बैंक के पक्ष में बकाया राशि और भविष्य के ब्याज सहित 6% प्रति वर्ष की दर से एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। बंधककर्ता के 10 आना शेयरों की बिक्री की प्रारंभिक डिक्री भी विद्वान पंचम अतिरिक्त अवर न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22.6.1981 को या उसके आसपास पारित की गई थी, जिसके बाद बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए अंतिम डिक्री दिनांक 4.8.1982 को वाद संख्या 88/9/1977-80 में पारित की गई थी।

इसके विरुद्ध उत्तरदाताओं द्वारा प्रथम अपील दायर की गई और दिनांक 22.5.1988 के एक आदेश द्वारा एक खंडपीठ ने निर्देश दिया कि डिक्री राशि दो किश्तों में भुगतान की जाए। कथित तौर पर, उक्त निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं किया गया। हालाँकि, बैंक द्वारा दायर

एक निष्पादन आवेदन पर, कुल 57.12 एकड़ भूमि में से 30 एकड़ भूमि लगभग दिनांक 7.6.1988 को नीलामी बिक्री के लिए रखी गई, जिसमें याचिकाकर्ता 1,61,598.53 रुपये की राशि की पेशकश करके सबसे अधिक बोली लगाने वाला बन गया। उक्त नीलामी बिक्री की पुष्टि निष्पादन न्यायालय द्वारा दिनांक 7.7.1988 को की गई थी जिसके अनुसरण में, अपीलकर्ता ने राशि जमा कर दी। इसके बाद, बंधककर्ता के भाई ने उक्त निष्पादन मामले में एक आपत्ति दर्ज की, जो कथित तौर पर दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 47 के अनुसार थी नीलामी बिक्री को अपास्त करने के लिए, जिसे विविध दीवानी वाद सं. 11/88 के रूप में चिह्नित किया गया था। उक्त आवेदन को दिनांक 27.8.1988 के निर्णय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पक्षकारों को अपने पिता से विरासत में मिली 95.20 एकड़ जमीन को ध्यान में रखते हुए, 60 एकड़ जमीन बंधककर्ता की थी जिसमें से केवल 30 एकड़ की नीलामी की गई थी। अपीलकर्ता ने दिनांक 11.12.1990 के आसपास पारित आदेश के अनुसार नीलाम की गई जमीन का कब्जा ले लिया। दिनांक 27.8.1988 के निर्णय और आदेश पर सवाल उठाते हुए, उत्तरदाताओं ने वर्ष 1990 में उच्च न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका आवेदन दायर किया, जिसे 1990 की समीक्षा याचिका सं.1700 के रूप में चिह्नित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.5.1992 के निर्णय के कारण नीलामी बिक्री को अलग रखा गया था, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता द्वारा निम्नलिखित उपाय का सहारा लिया जाए।

> "(ए) अरुण प्रकाश पांडे के हिस्से से एक अलग क्षेत्र निकालने के लिए एक अलग वाद दायर करके विभाजन की मांग करना या
>
> (बी) अरुण प्रकाश पांडे के तख्त में उसके द्वारा खरीदे गए क्षेत्र को शामिल करने के लिए उपरोक्त विभाजन वाद में एक आवेदन दायर करना।"

अपीलकर्ता ने इसके विरुद्ध एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) सं. 8119/92 के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसका निपटारा दिनांक 25.6.1992 के एक आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें कहा गया था:

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, आक्षेपित आदेश का लाभ उठाने के लिए इस याचिका को वापस लेते हैं। विशेष अनुमति याचिका को वापस लेते हुए निपटाया जाता है।"

अपीलकर्ता का तर्क है कि कब्जा प्राप्त करने के बाद, उसने भूमि को कृषि योग्य बनाया, जिसके लिए उसने लगभग 2 लाख रुपये खर्च किए थे।

हालाँकि, यहाँ अपीलकर्ता ने विभाजन वाद संख्या 17/1976 में पारित डिक्री को अपास्त करने और 1990 के दीवानी समीक्षा संख्या 1700 के आदेश को अपास्त करने के लिए स्वत्व वाद संख्या 4/1994 दायर किया।

अपीलकर्ता ने उक्त विभाजन वाद संख्या 17/76 में *अन्य बातों के साथ-साथ* इस आधार पर भी एक आवेदन दायर किया कि दिनांक 19.7.78 की प्रारंभिक डिक्री एक मिलीभगतपूर्ण और कपटपूर्ण थी और उसके आधार पर शुरू की गई अंतिम डिक्री कार्यवाही शून्य और अवैध है; *अन्य बातों के साथ-साथ* इस आधार पर कि बंधककर्ता के पिता उगम प्रकाश पांडे की वर्ष 1944 में मृत्यु हो जाने के कारण, केवल बंधककर्ता ही संपत्तियों का उत्तराधिकारी था, न कि उसकी बहनें क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 तब से लागू नहीं हुआ था:। उक्त तर्क के समर्थन में अपीलकर्ता ने विभिन्न दस्तावेज दायर किए। उक्त आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया:

"(ए) उगम पांडे की मृत्यु वर्ष 1944 में हुई थी, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं हुआ था।

(बी) दस्तावेज़ यह साबित करते हैं कि वादी श्रीमती सावित्री देवी का वादग्रस्त संपत्ति में कोई हित नहीं था और विभाजन के वाद में तैयार की गई प्रारंभिक डिक्री

कपटपूर्ण, मिलीभगत से किए गए और शून्य है। अरुण प्रकाश पांडे के साथ मिलीभगत करके वादपत्र में और उसके साक्ष्य में उगम पांडे की मृत्यु को छिपाकर धोखाधड़ी करके दस्तावेज़ प्राप्त किए गए।

(सी) प्रारंभिक डिक्री के आधार पर वादी द्वारा शुरू की गई अंतिम डिक्री कार्यवाही कपटपूर्ण और शून्य है और इसलिए अंतिम डिक्री कार्यवाही रद्द की जाती है।"

इसके विरुद्ध एक दीवानी समीक्षा आवेदन दायर किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। एस.एल.पी. (दीवानी) सं. 6535/1999 उक्त आदेश से उत्पन्न होती है।

इसके अलावा, अपीलकर्ता ने प्रथम अपील सं. 450/1981 में पारित दिनांक 22.5.1988 के आदेश की समीक्षा के लिए दीवानी समीक्षा आवेदन सं. 245/1998 दायर किया, जिसके तहत पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.6.1981 के निर्णय और प्रारंभिक डिक्री को संशोधित करते हुए निर्देश दिया कि डिक्री राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाए, *अन्य बातों के साथ-साथ* इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के पक्ष में बंधक संपत्ति की बिक्री से संबंधित तथ्य उसके संज्ञान में नहीं लाया गया है। उक्त दीवानी समीक्षा आवेदन को एक विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 10.5.1999 को खारिज कर दिया। एस.एल.पी. (दीवानी) सं. 20273/2000 उक्त आदेश से उत्पन्न होता है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. जी.सी. भरुका ने *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं ने न्यायालय से धोखाधड़ी करके डिक्री प्राप्त की है, अतः उन्हें इसका लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंधककर्ता के पिता की मृत्यु वर्ष 1944 में हो गई थी, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनकी बहनों के उनके सह-हिस्सेदार बनने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि बैंक के पक्ष में पारित प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध अपील की गई थी, परन्तु

कोई स्थगन नहीं दिया गया था, फिर भी संपत्ति को नीलामी में रखा जा सकता था और यदि न्यायालय की ओर से कुछ गलतियाँ भी हुई हों, तो भी अपीलकर्ता को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बहनों के कहने पर नीलामी बिक्री को अपास्त करने वाले दिनांक 27.8.1988 के निर्णय और आदेश को, इसलिए अवैध माना जाना चाहिए।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 22.6.1981 के निर्णय और आदेश को संशोधित करने में स्पष्ट त्रुटि की है। प्रथम अपील सं. 450/1981 में दिनांक 22 मई, 1988 का निर्णय पारित करके, जिसमें न्यायालय की नीलामी में गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री के प्रभाव और आशय पर विचार किए बिना बैंक को देय डिक्री राशि का भुगतान दो किश्तों में करने का निर्देश दिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ऐसा आदेश पक्षकारों की सहमति पर पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि संपत्तियां नीलामी में बेची गई थीं, अपीलकर्ता को उस पर अधिकार प्राप्त था। किसी भी स्थिति में, विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि, चूंकि पक्षकारों ने उपर्युक्त तथ्यों को दबाने का सहारा लिया है, इसलिए सहमति डिक्री अमान्य थी। और इस मामले के मद्देनजर, उच्च न्यायालय को अपने पहले के आदेश की समीक्षा करनी चाहिए थी।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राम लाल रॉय ने आग्रह किया कि चूँकि अपीलकर्ता ने प्रथम अपील में पारित निर्णय और डिक्री पर प्रश्न नहीं उठाया है, इसलिए इन अपीलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। श्री रॉय ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नीलामी बिक्री को दिनांक 21.5.1992 को ही अपास्त कर दिया गया था और उसके विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, पुनर्विचार आवेदन विचारणीय नहीं था। किसी भी स्थिति में, विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि चूँकि प्रथम अपील में पारित सहमति आदेश के अनुसरण

में उत्तरदाताओं ने पहले ही राशि जमा कर दी है, इस न्यायालय को अपने न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

न्यायालय में धोखाधड़ी करना और तथ्यों को छिपाना इन मामलों में शामिल मुख्य मुद्दे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, धोखाधड़ी हर गंभीर कार्य को दूषित कर देती है। धोखाधड़ी और न्याय कभी एक साथ नहीं रह सकते।

कपट ऐसा आचरण है, जो चाहे लिखित कथन द्वारा अथवा मौखिक कथन द्वारा किया गया हो, और जिसके परिणामस्वरूप अन्य व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, उस आचरण के प्रत्युत्तर में, किसी निश्चित एवं निर्णायक अभिमत या निर्णय को अपनाने के लिए प्रेरित हो जाए।

यह भी सर्वविदित है कि मिथ्याबयान स्वयं धोखाधड़ी है। वास्तव में, निर्दोष मिथ्याबयान भी धोखाधड़ी के विरुद्ध राहत का दावा करने का कारण बन सकता है।

कपटपूर्ण मिथ्याबयान को छल कहा जाता है और इसमें किसी व्यक्ति को जानबूझकर या लापरवाही से झूठ पर विश्वास करने और उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित करके उसे नुकसान पहुँचाना शामिल है। यदि कोई पक्ष ऐसे अभ्यावेदन करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह झूठा है, और उससे नुकसान होता है, हालाँकि जिस उद्देश्य से अभ्यावेदन किया गया था वह बुरा नहीं रहा होगा, तो इसे कानूनन धोखाधड़ी माना जाता है।

डेरी बनाम पीक, (1889) 14 एसी 337 में, यह अभिनिर्धारित किया गया:

> 'छल की कार्रवाई' में वादी को वास्तविक धोखाधड़ी साबित करनी होगी। धोखाधड़ी तब साबित होती है जब यह दर्शाया जाता है कि कोई झूठा बयान जानबूझकर, या उसकी सच्चाई पर विश्वास किए बिना, या लापरवाही से, इस बात की परवाह किए बिना किया गया है कि वह सच है या झूठ।
>
> लापरवाही से और उसे सच मानने के उचित आधार के बिना दिया गया झूठा बयान धोखाधड़ी का सबूत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह धोखाधड़ी ही हो। ऐसा बयान, अगर ईमानदारी से यह विश्वास करते हुए दिया गया हो कि वह सच है, तो

वह कपटपूर्ण नहीं है और उस व्यक्ति को धोखे की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता।

केर ऑन फ्रॉड एंड मिस्टेक के पृष्ठ 23 पर कहा गया है:

"*स्लिम बनाम क्राउचर* द्वारा प्रस्तुत वादों से प्राप्त होने वाला सच्चा और एकमात्र ठोस सिद्धांत यह है: कि कोई प्रतिनिधित्व न केवल तभी कपटपूर्ण होता है जब उसे बनाने वाला व्यक्ति जानता है कि वह झूठा है, बल्कि तब भी जब, जैसा कि जेसल, एम.आर. ने बताया, उसे पता होना चाहिए था, या यह मान लिया जाना चाहिए कि वह झूठा था। यह एक ठोस और बोधगम्य सिद्धांत है, और इसके अलावा, *डेरी बनाम पीक* के साथ असंगत नहीं है। एक झूठा कथन, जिसके बारे में किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए था कि वह झूठा है, और जिसके बारे में उसे यह मान लिया जाना चाहिए कि वह झूठा था, उस पर ईमानदारी से विश्वास नहीं किया जा सकता। लॉर्ड हर्शेल ने कहा, "विश्वास के आधारों पर विचार निस्संदेह यह पता लगाने में एक महत्वपूर्ण सहायता है कि क्या विश्वास वास्तव में मन में था। किसी व्यक्ति का केवल यह दावा कि उसने अपने द्वारा दिए गए कथन को सत्य माना, इस बात के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है कि उसने ऐसा किया था।"

बिगेलो ऑन फ्रॉडुलेंट कोवेंसेस के पृष्ठ । पर लिखा है:

"यदि तथ्यों के आधार पर औसत व्यक्ति का इरादा गलत होता, तो यह पर्याप्त है।"

आगे यह भी कहा गया है कि

"धोखाधड़ी की यह अवधारणा (और चूँकि यह लेखक की नहीं है, इसलिए वह इसके बारे में बिना किसी संकोच के बात कर सकता है); लगातार ध्यान में रखने से, कानून का प्रशासन कम कठिन हो जाएगा, या यूँ कहें कि इसका प्रशासन अधिक प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा, अंतिम विषय पर विस्तार से न बोलते हुए, यह 'नैतिक' धोखाधड़ी के संबंध में प्रचलित भ्रम को काफी हद तक दूर कर देगा, एक

ऐसा भ्रम जो, अन्य बातों के अलावा, अक्सर अधिवक्ताओं को 'कानून के साथ धोखाधड़ी' जैसी सुविधाजनक और वास्तव में उपयोगी लेकिन अक्सर अस्पष्ट भाषा की शरण लेने के लिए प्रेरित करता है। कानून के साथ धोखाधड़ी क्या है? धोखाधड़ी केवल अधिकारों के लिए सक्षम व्यक्ति के विरुद्ध ही की जा सकती है, और 'कानून के साथ धोखाधड़ी' अधिवक्ता को अंधकारमय बना देती है। अधिकांश मामलों में नैतिक धोखाधड़ी और कानून के साथ धोखाधड़ी के बीच इस अस्पष्ट अंतर का वास्तविक उद्देश्य, गलत कार्य करने के व्यक्ति के इरादे में धोखाधड़ी और संबंधित कार्य की स्पष्ट प्रवृत्ति में दिखाई देने वाली धोखाधड़ी के बीच का अंतर है।"

हाल ही में इस न्यायालय ने 3 सितंबर, 2003 को *राम प्रीति यादव बनाम उत्तर प्रदेश उच्च विद्यालय एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड एवं अन्य,* संयुक्त न्यायाधिकरण (2003) पूरक. 1 एससी 25 में प्रतिवेदित किए गए एक आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया:

"धोखाधड़ी लेखन या शब्दों द्वारा किया गया एक आचरण है, जो दूसरे व्यक्ति या प्राधिकारी को उसके आचरण के जवाब में शब्दों या लेखन द्वारा एक निश्चित निर्णायक रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है। हालाँकि लापरवाही धोखाधड़ी नहीं है, लेकिन यह धोखाधड़ी का सबूत हो सकती है। (*डेरी बनाम पीक,* (1889) 14 एसी 337 देखें)।

लाजरस एस्टेट बनाम बेरली, [1956] । ऑल ईआर 341 में, अपील न्यायालय ने कानून को इस प्रकार बताया:

मैं एक पल के लिए भी इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता कि "इस देश का कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति नहीं देगा। किसी मंत्री के आदेश पर न्यायालय का कोई भी निर्णय, यदि धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो, मान्य नहीं हो सकता। धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है।" न्यायालय धोखाधड़ी का पता लगाने से सावधान रहता है जब तक कि यह स्पष्ट रूप

से प्रमाणित न हो जाए; लेकिन एक बार यह सिद्ध हो जाने पर यह निर्णयों, अनुबंधों और सभी लेन-देन को दूषित कर देता है।"

एस.पी. चंगलवरैया नायडू बनाम जगन्नाथ, [1994] 1 एससीसी 1 में इस न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों, चाहे वह धार्मिक हो या लौकिक, से बच जाती है।

न्यायालय में धोखाधड़ी के कृत्य को हमेशा गंभीरता से लिया जाता है। किसी संपत्ति से संबंधित अन्य लोगों के अधिकारों को वंचित करने के उद्देश्य से की गई मिलीभगत या साजिश, उस लेन-देन को *शुरू से ही* अमान्य कर देगी। धोखाधड़ी और छल समानार्थी हैं।

आर्लिज एंड पैरी ऑन फ्रॉड में, पृष्ठ 21 पर कहा गया है:

"वास्तव में, यह शब्द कभी-कभी लगभग "धोखे" का पर्यायवाची प्रतीत होता है, जैसे कि धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करने के अपराध (अब निरस्त) में। यह सच है कि इस संदर्भ में "धोखाधड़ी" में कुछ प्रकार के आचरण शामिल थे जो झूठे बहाने नहीं थे, क्योंकि परिभाषा में "झूठे बहाने से, या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से" ऋण प्राप्त करने का उल्लेख था। उदाहरण के लिए, जोन्स में, एक व्यक्ति जो यह बताए बिना कि उसके पास पैसे नहीं हैं, भोजन का आदेश देता है, उसे धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त करने का दोषी माना जाता है, लेकिन झूठे बहाने से भोजन प्राप्त करने का नहीं: उसका आचरण, यद्यपि धोखाधड़ीपूर्ण था, झूठे बहाने के बराबर नहीं था। इसी प्रकार, यह सुझाव दिया गया है कि धोखाधड़ी की साजिश का आरोप तब लगाया जा सकता है जब जनता के सामने एक "झूठा दिखावा" प्रस्तुत किया गया हो (उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय प्रतिष्ठित और विश्वसनीय प्रतीत होता है जबकि वास्तव में वह ऐसा नहीं है) लेकिन झूठे बहाने जैसा ठोस कुछ भी नहीं हुआ हो। हालाँकि, धोखे की अवधारणा (जैसा कि चोरी अधिनियम 1968 में परिभाषित किया गया है) झूठे बहाने की अवधारणा से कहीं अधिक व्यापक है, जिसमें (*अन्य बातों के साथ-साथ*) उत्तरदाता

के इरादों के बारे में गलत बयानी भी शामिल है; जोन्स और "झूठे बहाने" दोनों को अब धोखे से संपत्ति प्राप्त करने के मामलों के रूप में माना जा सकता है।

यद्यपि किसी दिए गए मामले में धोखा धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता है, धोखाधड़ी सभी न्यायसंगत सिद्धांतों के लिए अभिशाप है और धोखाधड़ी से दूषित कोई भी मामला किसी भी न्यायसंगत सिद्धांत के प्रयोग द्वारा कायम नहीं रखा जा सकता या बचाया नहीं जा सकता जिसमें *पुनर्न्यायिकता* भी शामिल है।

श्रीमती श्रिष्ट धवन बनाम सुश्री शॉ ब्रदर्स, एआईआर (1992) एससी 1555 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि;

"धोखाधड़ी और मिलीभगत किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था में सबसे गंभीर कार्यवाही को भी दूषित कर देती है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो मानव आचरण का वर्णन करती है।"

"एस.पी. चें*गलवरैया नायडू बनाम जगन्नाथ*, [1994] 1 एसएससी 1 में इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था;

"... "मुकदमेबाजी की अंतिमता" के सिद्धांत को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि यह बेईमान वादियों के हाथों में धोखाधड़ी का साधन बन जाए। न्यायालय पक्षों के बीच न्याय प्रदान करने के लिए हैं। जो कोई भी न्यायालय में आता है, उसे निष्कपट आना चाहिए। हमें यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि अक्सर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है। संपत्ति हड़पने वाले, कर चोरी करने वाले, बैंक ऋण न चुकाने वाले और जीवन के सभी क्षेत्रों के अन्य बेईमान व्यक्ति न्यायालय की प्रक्रिया को अवैध लाभ को अनिश्चित काल तक बनाए रखने का एक सुविधाजनक साधन पाते हैं। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस व्यक्ति का मामला झूठ पर आधारित है, उसे न्यायालय जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसे वाद के किसी भी चरण में तुरंत बाहर निकाला जा सकता है... धोखाधड़ी

किसी चीज़ को हासिल करने के इरादे से जानबूझकर किया गया एक धोखा है किसी दूसरे का अनुचित लाभ उठाकर। यह दूसरे के नुकसान से लाभ पाने के लिए किया गया धोखा है। यह लाभ पाने के इरादे से की गई धोखाधड़ी है... एक वादी, जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, वह वाद से संबंधित अपने द्वारा निष्पादित सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। यदि वह दूसरे पक्ष को लाभ पहुँचाने के लिए कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ छुपाता है, तो वह न्यायालय के साथ-साथ विरोधी पक्ष के साथ भी धोखाधड़ी करने का दोषी होगा।"

इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, [1996] 5 एससीसी 550 में, इस न्यायालय ने *लाजरस एस्टेट्स* (उपरोक्त) और अन्य मामलों का संदर्भ देते हुए यह टिप्पणी की कि 'चूँकि धोखाधड़ी न्यायालय की कार्यवाही की गंभीरता, नियमितता और सुव्यवस्था को प्रभावित करती है इसलिए यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है और न्यायालयों के पास धोखाधड़ी करके प्राप्त आदेश को अपास्त करने की अंतर्निहित शक्ति है, और जहाँ न्यायालय को किसी पक्ष द्वारा गुमराह किया जाता है या न्यायालय स्वयं कोई ऐसी गलती करता है जिससे किसी पक्ष को नुकसान पहुँचता है, तो न्यायालय के पास अपने आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति है।'

आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया:

"भारत में न्यायपालिका के पास, विशेष रूप से धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत, अपने फैसले या आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति भी है, यदि वह न्यायालय से धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया हो। वाद या कार्यवाही में किसी पक्षकार के साथ धोखाधड़ी के मामले में, न्यायालय प्रभावित पक्ष को धोखाधड़ी से प्राप्त डिक्री को अपास्त करने के लिए एक अलग वाद दायर करने का निर्देश दे सकता है। अंतर्निहित शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं, जो सभी न्यायालयों में, विशेष रूप से उच्च अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों में विद्यमान होती हैं। ये शक्तियाँ विधान से नहीं, बल्कि

न्यायाधिकरणों या न्यायालयों की प्रकृति और संरचना से उत्पन्न होती हैं ताकि वे अपनी गरिमा बनाए रख सकें, अपनी प्रक्रिया और नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें, अपने अधिकारियों को अपमान और गलत व्यवहार से बचा सकें और अनुचित व्यवहार के लिए दंडित कर सकें। यह शक्ति न्यायालय के कार्यों के व्यवस्थित प्रशासन के लिए आवश्यक है।"

चित्तरंजन दास बनाम दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं अन्य, [99 सीडब्ल्यूएन 897] में, यह अभिनिर्धारित किया गया है:

"ऐसे मामलों में किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को छिपाना, जो याचिकाकर्ता की सेवा की शर्तों को प्रभावित करता है, धोखाधड़ी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन करना आवश्यक नहीं है।

यह सर्वविदित है कि धोखाधड़ी सभी गंभीर कृत्यों को दूषित कर देती है। इस प्रकार, भले ही याचिकाकर्ता की जन्मतिथि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा विवरणी में दर्ज की गई हो, वह पवित्र नहीं है और न ही उत्तरदाता कंपनी इसके लिए बाध्य होगी।"

उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों में उठाए गए प्रश्नों पर विचार किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा दायर हस्तक्षेप का आवेदन, जो आदेश XXVI, नियम 13 और 14(2) और आदेश XX, नियम 18 के अंतर्गत माना जाता है, अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि ये न्यायालय को किसी प्रारंभिक डिक्री को इस आधार पर अपास्त करने का कोई अधिकार नहीं देते कि वह धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। लेकिन एक बार जब उपर्युक्त सिद्धांतों को प्रभावी कर दिया जाता है, तो निर्विवाद रूप से न्यायालय को इसके संबंध में अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र माना जाना चाहिए।

मनोहर लालचोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, एआइआर (1962) एससी 527 में, कानून को निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है:

"दीवानी प्रक्रिया संहिता निस्संदेह संपूर्ण नहीं है: यह सभी स्थितियों के संबंध में मार्गदर्शन के लिए नियम निर्धारित नहीं करती न ही यह सभी संभावित मामलों के निर्णयों के लिए नियम प्रदान करने का प्रयास करती है जो उत्पन्न हो सकते हैं। दीवानी न्यायालयों को ऐसे आदेश पारित करने का अधिकार है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, लेकिन जहाँ किसी विशेष स्थिति से निपटने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान किया गया है, वहाँ संहिता का पालन किया जाना चाहिए, और उससे विचलन स्वीकार्य नहीं है।

शारदा बनाम धर्मपाल, [2003] 4 एससीसी 493 में, तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसके हम दोनों पक्षकार हैं, ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को वैवाहिक न्यायालय द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराने का निर्देश देना निहित है, यह कहते हुए:

"अन्यथा भी न्यायालय एक उचित निर्देश जारी कर सकता है ताकि वह स्वयं इस बारे में संतुष्ट हो सके कि क्या उपचार के अलावा उसे कानूनी सहायता के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि वह अपनी अक्षमता के कारण किसी अन्यायपूर्ण आदेश के अधीन न हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मानसिक बीमारी के मामले में न्यायालय के पास पक्षकार की जाँच करने या किसी योग्य चिकित्सक से उसकी जाँच कराने का पर्याप्त अधिकार है। हमारा विचार है कि किसी उचित मामले में न्यायालय पक्षकार के कहने पर भी ऐसी प्रक्रिया का सहारा ले सकता है।

इसके अलावा, न्यायालय को दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत भी अपेक्षित शक्ति प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह *स्वप्रेरणा* से या अन्यथा ऐसा निर्देश जारी कर सके जो, उनके अनुसार, सत्य की ओर ले जाए।

एक बार जब यह अभिनिर्धारित कर लिया जाता है कि न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके निर्णय और डिक्री प्राप्त की गई है, तो यह स्वाभाविक है कि *पूर्व-न्याय* के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने अपने द्वारा पारित पूर्व आदेशों का उल्लेख करके एक गंभीर त्रुटि की है जिससे अपीलकर्ता के लिए न्याय के द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इसलिए, हमारा मत है कि दिनांक 10.12.1998 का आक्षेपित निर्णय स्थायी नहीं रखा जा सकता।

चूँकि दीवानी समीक्षा सं. 245/1998 में पारित दिनांक 10.5.1999 का आदेश मान्य है, इसलिए इतना कहना ही पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए था कि क्या नीलामी क्रेता के अधिकार को उसकी अनुपस्थिति में पारित सहमति आदेश के कारण अमान्य किया जा सकता था। अपीलकर्ता प्रथम अपील में पक्षकार नहीं था, वह समझौते का भी पक्षकार नहीं था।

जैसा कि सर्वविदित है, सहमति आदेश पक्षकारों के बीच एक समझौता होता है जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होती है। यहाँ अपीलकर्ता ने समीक्षा आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपील के पक्षकारों ने नीलामी बिक्री और उसकी पुष्टि को छुपाया था। प्रथम अपील दायर करने के बाद घटित घटनाओं के प्रभाव जिसके परिणामस्वरूप तृतीय पक्ष के अधिकार का सृजन हुआ, उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अनिवार्य था। किसी तृतीय पक्ष के अधिकार को सहमति से अमान्य नहीं किया जा सकता। इसलिए, उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता के तर्क पर उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय अपने आदेश की समीक्षा के उद्देश्य से इन प्रश्नों पर स्वयं विचार करने के लिए बाध्य था।

द्वारका प्रसाद अग्रवाल (डी) विधिक प्रतिनिधि के द्वार और अन्य बनाम बी.डी. अग्रवाल एवं अन्य , (2003] 6 एससीसी 230 में, यह टिप्पणी की गई थी:

"उच्च न्यायालय द्वारा कई गंभीर मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर एक छोटा रास्ता अपनाया कि उक्त समझौता द्वारका प्रसाद अग्रवाल पर बाध्यकारी नहीं था और इसलिए कोई रिट जारी नहीं की गई। उक्त समझौते के दर्ज होने का परिणाम स्पष्ट था। न केवल इसके अनुसरण में या इसके आगे भी, उक्त समझौते के दर्ज होने का परिणाम स्पष्ट था। समाचार पत्र निबंधक, नई दिल्ली ने दिनांक 3.9.1992 को एक आदेश पारित किया; इसे उच्च न्यायालय का एक निर्णय माना गया, जिसकी उत्तरदाताओं ने उन वाद को वापस लेने के उद्देश्य से सहायता ली थी, जिनमें विभिन्न प्रकार के विवादित तथ्य और कानून के प्रश्न जिनमें समझौतों की वास्तविकता या अन्यथा शामिल थे प्रश्नाधीन थे और जिन पर निर्णय की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय को पुनर्विचार आवेदन का निपटारा करते समय, स्वयं इस बात पर भी विचार करना था कि क्या यहाँ अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधारों पर किया गया कथित समझौता वैध था। बिना किसी विचार-विमर्श के, उच्च न्यायालय ने यह मान लिया कि समझौता वैध था। इसने स्वयं के समक्ष सही प्रश्न नहीं रखा जिससे वह तथ्यों के निष्कर्ष पर पहुँच सके जिसके परिणामस्वरूप सही उत्तर प्राप्त हो सके और इस प्रकार, यह कानून में गलत दिशा-निर्देशन के समान होगा।"

आगे यह भी कहा गया:

"अब यह सर्वविदित है कि बिना अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेश अमान्य है। उसके अनुसरण में या उसके आगे पारित कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई भी अमान्य होगी। इस मामले में, चूँकि उच्च न्यायालय के पास पूर्व में बताए गए कारणों से समझौता दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और विशेष रूप से चूँकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई रिट जारी करने की आवश्यकता नहीं थी कि सार्वजनिक कानून के उपाय का सहारा नहीं लिया जा सकता था, इसलिए

आक्षेपित आदेशों को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना माना जाना चाहिए और उन्हें अपास्त किया जाना चाहिए। उसके अनुसरण में या उसके आगे लिए गए सभी आदेशों और कार्रवाइयों को भी पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना घोषित किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप उन्हें **अपास्त** किया जाना चाहिए। उन्हें ऐसा ही घोषित किया जाता है।"

यह दोहराना होगा कि न्यायालय में धोखाधड़ी करके प्राप्त कोई भी आदेश क़ानून की नज़र में भी अमान्य है।

यह सच है कि सहमति आदेश के अनुसरण में या उसके अनुपालन में, उत्तरदाताओं ने राशि जमा कर दी थी और राज्य सरकार ने उसे हड़प लिया है। न्यायालय पर धोखाधड़ी के प्रभाव और पक्षकारों के आचरण से संबंधित क़ानूनी मुद्दे अभी भी विचाराधीन हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय को पक्षकारों के बीच न्यायसम्य को समायोजित करना आवश्यक था। बैंक स्वयं को अनुचित रूप से समृद्ध भी नहीं कर सकता; बंधक के प्रारंभिक आदेश को लागू करते समय, वह नीलामी क्रेता के खर्च पर निर्णय-ऋणदाताओं से डिक्री राशि वसूलने का भी सहारा नहीं ले सकता।

ऐसी स्थिति में भी, न्यायालय को कोई ऐसा उपाय ढूँढना पड़ सकता है जो न्यायसंगत और समतापूर्ण हो।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय '*न्यायालय का कोई कार्य किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा*' के सिद्धांत पर ध्यान देने में विफल रहा।

राजेश डी. दरबार एवं अन्य बनाम नरसिंहराव कृष्णजी कुलकर्णी एवं अन्य, जे.टी. (2003) 7 एससी 209 में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

"न्यायालय बाद की घटनाओं पर ध्यान दे सकते हैं और तदनुसार राहत प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इन सुस्थापित सिद्धांतों में एक शर्त है। ऐसा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर किया गया

है। हालाँकि, यह न्यायसंगत सिद्धांत न्यायालय द्वारा किसी क़ानून द्वारा पहले से ही निहित अधिकारों पर निर्णय लेने के मार्ग में बाधक नहीं बन सकता। इस सुस्थापित स्थिति को हमें तब रोकने की आवश्यकता नहीं है, जब अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए दूसरे बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं हो सकता कि न्यायालय के किसी कार्य के कारण किसी पक्ष को कष्ट नहीं पहुँचाया जा सकता। समता का एक सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसका नाम है, *एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेवाबिट*, जिसका अर्थ है कि न्यायालय का कार्य किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुँचाएगा। यह सिद्धांत न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित है जो विधि प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शक का कार्य करता है। दूसरा सिद्धांत है, *लेक्स नॉन कॉगिट एड. इम्पॉसिबिलिया,* अर्थात् विधि किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करती जो वह स्वयं नहीं कर सकता। उपर्युक्त सिद्धांतों की प्रयोज्यता को इस न्यायालय ने *राज कुमार डे एवं अन्य बनाम तारापाका डे एवं अन्य, [1987] 4 एससीसी 398; गुरशरण सिंह बनाम नई दिल्ली नगर निगम समितियाँ, [1996] 2 एससीसी 459 और मोहम्मद गाजी बनाम राज्य मध्य प्रदेश एवं अन्य,* [2000] 4 एससीसी 342 में अनुमोदित किया है।

उपर्युक्त कारणों से, हमारा मत है कि आलोचना किए गए निर्णयों को बरकरार नहीं रखा जा सकता, जिन्हें तदनुसार **अपास्त** किया जाता है। अब उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में की गई टिप्पणियों के आलोक में इन मामलों पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। -• ये 'अपीलें' स्वीकार की जाती हैं। - कोई लागत नहीं।

बी.एस. - अपीलें स्वीकार की जाती हैं:

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।